958/973

दैनिक जागरण (दैनिक समाचार पत्र) 09-10-2015
पृष्ठ संख्या – 12

खेती संग पेड़ लगाने से किसानों की सुधरेगी दशा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : खेती के साथ पेड़ लगाकर किसानों की दशा सुधारने के लिए तुरंत नई राष्ट्रीय वानिकी नीति को लागू करने और वन नीति में पर्याप्त संशोधन की सख्त जरूरत है। देश की खाद्य सुरक्षा, पौष्टिकता, ऊर्जा और पर्यावरण सुरक्षा के लिए परती व बंजर भूमि के साथ खेती वाली जमीन में भी पेड़ लगाने की योजना को और प्रोत्साहन की जरूरत है। सरकार की इस मुहिम से देश में किसानों की दशा सुधरेगी।

कृषि वानिकी पर आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कहा गया कि ज्यादातर देश एग्रो फॉरेस्ट्री से अपने यहां वन का क्षेत्रफल बढ़ाकर राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस सम्मेलन में कृषि क्षेत्र से जुड़े दुनियाभर की कई प्रमुख संगठन हिस्सा ले रहे हैं। ज्यादातर एशियाई देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस विमर्श में जाने-माने वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं।

टीएएएस के प्रमुख डॉक्टर राज परोदा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री मुफीद साबित होगी। हमारी सरकार ने वर्ष 2030 तक 33 फीसद कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए आक्रामक रणनीति बनाने की जरूरत है। बंजर व खराब पड़ी भूमि में वनीकरण की सख्त जरूरत है, जिसे एग्रो फॉरेस्ट्री से पूरा किया जा सकता है। भारत में 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि में खेती होती है, जिसके 10 फीसद हिस्से पर एग्रो फॉरेस्ट्री के माफिक पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य है। डॉ. परोदा ने कहा कि पशुओं की घटती संख्या के चलते कंपोस्ट खाद की कमी से मिट्टी में कार्बन की भारी कमी हो गई है। मिट्टी में 0.5 से 0.7 फीसद कार्बन है, जबकि चीन में 1.5 से तीन फीसद तक कार्बन की मात्रा है। खेतों के आसपास की खाली जमीनों में अथवा फसलों के साथ पेड़ लगाने की जरूरत है। डॉ. परोदा ने कहा 'कृषि प्रधान देश कृषक प्रधान कब बनेगा?' बिना इसके देश की खेती अथवा खेतिहरों का भला होने वाला नहीं है।

- कार्बन गैस उत्सर्जन में कटौती लक्ष्य के लिए कृषि वानिकी जरूरी
- राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति लागू करने और वन नीति में ढील देने की जरूरत

...तो चिकन की तरह भुन जाएंगे हम

लीमा, एजेंसियां : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की प्रमुख क्रिस्टीन लगार्ड ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर हम चिकन में बदल जाएंगे। हम तले, भुने और सेंके जाएंगे। वे पेरू के लीमा में बुधवार को आइएमएफ और वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठक को संबोधित कर रही थीं। लगार्ड ने इस दौरान कार्बन कर की वकालत करते हुए सरकारों से जीवाश्म ईंधन से सब्सिडी हटाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन पर लगाए जाने वाले कर को शुरू करने का यह सही समय है। इससे जलवायु परिवर्तन से निपटने के साथ-साथ राजस्व जुटाने में भी मदद मिलेगी। लगार्ड ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया के अधिकांश देश राजकोषीय घाटे से परेशान हैं और राजस्व जुटाने के विकल्पों की तलाश कर रहे हैं कार्बन कर को शुरू किया जा सकता है। इससे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2020 तक गरीब देशों के लिए सौ अरब डॉलर (करीब छह लाख 51 हजार करोड़) का फंड जुटाने में अमीर देशों को मदद भी मिलेगी।

1. निदेशक, भा० कृ० अनु० संस्थान
2. संयुक्त निदेशक, (प्रसार) ,,
3. ,, , (शिक्षा) ,,
4. ,, , (अनुसंधान) ,,
5. प्रभारी, पी० जी० आई० ,,
6. प्रभारी, कैटेट ,,
7. प्रभारी, ए० के० एम० यू ,,

[illegible] 9/10/15
द्वारा प्रभारी समाचार पत्र प्रकोष्ठ